भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 173
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

देश में बेरोजगारी

173. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश अभूतपूर्व रूप से बढ़ती बेरोजगारी की चपेट में है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संगठित/असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी चरम पर है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान बेरोजगारी में कई गुणा वृद्धि हुई है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(च) इससे उबरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (च): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का संगठित/असंगठित क्षेत्र सहित अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

(% में)

वर्ष	यूआर
2017-18	6.0
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1
2022-23	3.2

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त तालिका के आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पे-रोल डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर को कवर करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 1.3 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए। इसके साथ-साथ, पिछले साढ़े छह वर्षों के दौरान (सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक) 6.2 करोड़ से अधिक शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए हैं, जो रोजगार की औपचारिकता में वृद्धि का संकेत देता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के रुझान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****